मेहिंदर सिंह सुल्लर जे. के समक्ष।

बलबीर सिंह विश्लेषक, हरियाणा कार्यालय * विश्लेषक, हरियाणा-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और *अन्य-उत्तरदाता*

1991 की सीडब्ल्यूपी संख्या 15603

21 अप्रैल; 2011

भारत का संविधान - अनुच्छेद 14, 16, 226 और 309 - याचिकाकर्ता को विश्लेषक के रूप में नियुक्त किया गया - याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रतिवादी ने पिछली तारीख से विश्लेषक के रूप में मनमाने ढंग से पदोन्नत किया - याचिकाकर्ता को प्रतिवादी वरिष्ठ घोषित किया - पूर्वव्यापी पदोन्नति आदेश को रद्द कर दिया - याचिका स्वीकार कर ली गई। r

माना जाता है कि एक बार, आधिकारिक प्रतिवादी ठोस साक्ष्य द्वारा यह साबित करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं कि विश्लेषक के कैडर में पदोन्नति कोटा का कोई भी पद 1982 से खाली था, लेकिन लिखित बयान में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि विश्लेषक के कैडर में पदोन्नति कोटा में कोई पद 1985 तक उपलब्ध नहीं था, उस स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है और आधिकारिक उत्तरदाताओं को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि प्रतिवादी नंबर 3 को पूर्वव्यापी रूप से सही ठहराया गया था इस संबंध में 30 अक्तूबर, 1984 से पदोन्नति।

(पैरा नं. 23)

आगे कहा गया कि यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि आधिकारिक प्रतिवादी प्रतिवादी नंबर 3 को पूर्वव्यापी पदोन्नति देने में गहरी कानूनी त्रुटि में फिसल गया, याचिकाकर्ता को उसके लिए जूनियर बना दिया, उसे कोई नोटिस जारी किए बिना और इस संबंध में याचिकाकर्ता के साथ महान अन्याय को बनाए रखा। इस प्रकार, आक्षेपित पदोन्नति आदेश न केवल मनमाना, अवैध है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ भी है, जिसे मामले की प्राप्त परिस्थितियों में कानूनी रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा नं. 29)

याचिकाकर्ता के वकील कृष्ण कुमार चहल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आरके मलिक।

कीर्ति सिंह, उप महाधिवक्ता, हरियाणा *प्रतिवादी नंबर 1 और 2।*

सीएम चोपड़ा, एडवोकेट *प्रतिवादी नंबर 3*

***मेहिंदर सिंह सुल्लर जे.* (मौखिक)**

तत्काल रिट याचिका में शामिल और रिकॉर्ड से निकलने वाले मुख्य विवाद को तय करने के सीमित उद्देश्य के लिए जिन तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह विज्ञापन के मद्देनजर और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की सिफारिश पर है। , हरियाणा (संक्षिप्तता के लिए "बोर्ड"), याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र दिनांक 29.4.1986 के आधार पर, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा-प्रतिवादी संख्या 2 (संक्षेप में "निदेशक") द्वारा विश्लेषक के पद पर नियुक्त किया गया था। (अनुलग्नक पी1)। नियुक्ति पत्र के अनुसरण में, याचिकाकर्ता 6.5.1986 को विश्लेषक के रूप में अपनी सेवा में शामिल हो गया। इसके बाद, कुसुम कुमार-प्रतिवादी नंबर 3, जो पहले वरिष्ठ विश्लेषणात्मक सहायक के रूप में कनिष्ठ पद पर कार्यरत थे, को भी आदेश दिनांक 17.12.1986 (अनुलग्नक पी 2) के माध्यम से विश्लेषक के

पद पर पदोन्नत/समायोजित किया गया था। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 3 ने विश्लेषक के पद पर याचिकाकर्ता के कनिष्ठ के रूप में कार्य किया।

2. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अचानक सितंबर, 1988 के महीने में, प्रतिवादी नंबर 3 को एक अन्य कार्यालय आदेश दिनांक 16.9.1988 (अनुलग्नक पी 3) के माध्यम से 30.10.1984 से पिछली तारीख से मनमाने ढंग से विश्लेषक के रूप में पदोन्नत किया गया था। निदेशक ने 13.12.1988 को एक और पत्र (अनुलग्नक पी 4) जारी किया, जिसमें सार्वजनिक विश्लेषक को सूचित किया गया कि प्रतिवादी नंबर 3 विश्लेषकों की वरिष्ठता सूची में अशोक कुमार से नीचे और याचिकाकर्ता बलबीर सिंह से ऊपर होगा।

3. इसलिए, निदेशक (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 की पूर्वव्यापी पदोन्नति से असंतुष्ट, याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी 5 और पी 6) पेश किया, जिसे हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त और सचिव ने खारिज कर दिया। (प्रतिवादी संख्या 1), पत्र दिनांक 5.6.1991 (अनुलग्नक पी7) के माध्यम से (7.6.1991 को अवगत कराया गया)। याचिकाकर्ता ने फिर से अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी8) पेश किया और इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला भी समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

4. क्रमिक रूप से, याचिकाकर्ता संतुष्ट महसूस नहीं कर रहा था और उसने वर्तमान रिट याचिका दायर की, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधानों को लागू करते हुए, विश्लेषक के पद पर प्रतिवादी नंबर 3 को पूर्वव्यापी पदोन्नति देने वाले आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी 3) को चुनौती दी गई। भारत।

5. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामला, संक्षेप में जहां तक प्रासंगिक है, यह था कि उसे बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा विश्लेषक के रूप में नियुक्त किया गया था और 6.5.1986 को इसमें शामिल हो गया था, जबकि प्रतिवादी नंबर 3 पर काम कर रहा था। वरिष्ठ विश्लेषणात्मक सहायक का

निचला पद। इसके लगभग सात महीने बाद, उन्हें (प्रतिवादी नंबर 3) भी विश्लेषक के रूप में पदोन्नत किया गया। इस प्रकार, वह विश्लेषक के कैडर में उनसे जूनियर थे। यह दावा किया गया था कि हालांकि कोई पद नहीं था, निदेशक ने अवैध रूप से उन्हें 30.10.1984 से अपने पीछे पूर्वव्यापी पदोन्नति प्रदान की और याचिकाकर्ता से वरिष्ठ बना दिया, वह भी बिना कोई नोटिस जारी किए या सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना। उसे, एकपक्षीय आदेश (अनुलग्नक पी3) के आधार पर, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताया गया था। 13.11.1967 (अनुलग्नक पी 9) के कार्यकारी निर्देशों को जारी करने के अलावा, प्रश्न में पद के लिए उत्तरदाताओं द्वारा कोई वैधानिक नियम नहीं बनाए गए थे, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि विश्लेषक के 75% पद भरे जाने थे। सीधी भर्ती का मार्ग और शेष 25% पद विश्लेषक संवर्ग में पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने थे।

6. याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 1976, 1978, 1983 और 1984 में निदेशक द्वारा बनाए गए मसौदा नियम, जिन्हें सरकार द्वारा कभी अनुमोदित नहीं किया गया था, को किसी भी तरह से संकेतित संवर्ग के पद पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह दावा किया गया था कि विश्लेषकों के पदों के विज्ञापन, जिसमें याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था, को भारत भूषण गोयल और एक अन्य ने 1985 के सीडब्ल्यूपी संख्या 4286 के माध्यम से चुनौती दी थी। उस याचिका में, राज्य सरकार/प्रतिवादियों ने एक याचिका दायर की थी। इस आशय का विस्तृत लिखित विवरण (अनुलग्नक पी10) कि विश्लेषक के कैडर में अक्टूबर, 1985 तक पदोन्नत कोटा का कोई पद उपलब्ध नहीं था।

7. विभिन्न प्रकार के आरोप लगाना और कुल मिलाकर घटनाओं का क्रम बताना, याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 3 को पूर्वव्यापी पदोन्नति देने वाला विवादित आदेश (अनुलग्नक पी 3) न केवल मनमाना, अवैध था बल्कि प्राकृतिक न्याय के नियमों के खिलाफ था। भी। उपरोक्त आधारों के

आधार पर, याचिकाकर्ता ने ऊपर बताए गए तरीके से आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी 3) को चुनौती देने की मांग की।

8. उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के दावे का विरोध किया और अपने संबंधित लिखित बयान दाखिल किए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 6.5.1986 को विश्लेषक के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से याचिकाकर्ता की नियुक्ति/ज्वाइनिंग और प्रतिवादी नंबर 3 की प्रारंभिक पदोन्नति के तथ्य को स्वीकार किया गया। 17.12.1986 को विश्लेषक पद पर। हालाँकि, यह दलील दी गई थी कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 3 वर्ष 1982 में विश्लेषक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था, जो प्रासंगिक समय पर खाली पड़ा था, इसलिए, उसे 30.10.1984 से प्रभावी आदेश के तहत पदोन्नत किया गया था (अनुबंध पी3) उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के मद्देनजर। आधिकारिक उत्तरदाताओं का दलील यह था कि चूंकि याचिकाकर्ता के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ, इसलिए कोई नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को उचित रूप से खारिज कर दिया गया था और कहा गया था कि प्रतिवादी नंबर 3 को इस दिशा में सक्षम प्राधिकारी के आदेशों (अनुलग्नक आर 2 से आर 4) के मद्देनजर पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नत किया गया था।

9. उत्तरदाताओं का मामला आगे बढ़ता है कि निर्देश (अनुलग्नक पी9) को 28.2.1969 के कार्यकारी निर्देशों (अनुलग्नक आर3/5) द्वारा आगे संशोधित किया गया था। इसके बाद मसौदा नियम (अनुलग्नक आर 6) और 1978 के कार्यकारी निर्देशों को लागू बताया गया, जिसमें प्रावधान था कि विश्लेषक के 50% पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष 50% पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने थे। 1985 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4286 में दायर लिखित बयान (अनुलग्नक पी 10), जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 1985 तक पदोन्नत कोटा में कोई रिक्त पद नहीं था, को विभाग के डीलिंग सहायक की लापरवाही का परिणाम बताया गया था।

10. लिखित बयान की संपूर्ण सामग्री को पुन: प्रस्तुत करने के बजाय और पुनरावृत्ति से बचने के लिए, यह कहना पर्याप्त है कि निजी प्रतिवादी संख्या 3 ने बचाव/याचना की वही पंक्तियाँ अपनाईं जो आधिकारिक प्रतिवादी संख्या 1 के लिखित बयान में निहित थीं और 2. हालाँकि, यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि सभी उत्तरदाताओं ने रिट याचिका में निहित अन्य सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है और इसे खारिज करने की प्रार्थना की है। इस तरह मैं इस मामले को समझ गया हूं।

11. आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी 3) पर हमला करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कुछ दृढ़ता के साथ तर्क दिया है कि चूंकि याचिकाकर्ता 6.5.1986 को सीधी भर्ती के माध्यम से विश्लेषक के रूप में शामिल हुआ था, जबकि प्रतिवादी नंबर 3, जो वरिष्ठ विश्लेषणात्मक सहायक के रूप में कार्यरत थे, बाद में 17.12.1986 को विश्लेषक के पद पर पदोन्नत हुए और वह विश्लेषक के कैडर में याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे। तर्क यह है कि एकतरफा आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी 3) के आधार पर प्रतिवादी नंबर 3 को अचानक पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नत करना, याचिकाकर्ता को उससे कनिष्ठ बनाना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के गैर-मानसिक, मनमाना, अवैध और उल्लंघनकारी है। , जिसे बिना कोई नोटिस जारी किए या उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित कर दिया गया। दलील यह है कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठता के अधिकार को खत्म करने के लिए प्रतिवादी कथित मसौदा नियमों को लागू नहीं कर सकते, जिन्हें सरकार द्वारा कभी मंजूरी नहीं दी गई थी। तर्क के समर्थन में, उन्होंने बिहार राज्य और अन्य बनाम अखौरी सचिन्द्र नाथ और अन्य 1991 एससीसी (एल एंड एस) 1070 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है।

12. इसके विपरीत और आक्षेपित आदेश की सराहना करते हुए, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि चूंकि पदोन्नत कोटा में पद 1982 से रिक्त था, इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 को 1978 के निर्देशों और मसौदा नियमों के मद्देनजर, 1984 से पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नत किया जाना उचित

था। (अनुलग्नक आर6) और इस संबंध में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बीके भल्ला, गवर्नमेंट कॉलेज, गुरदासपुर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 1983(1) एसएलआर 636; के मामलों में भी इस अदालत के फैसले पर भरोसा जताया है; इस संबंध में लीला राम सलूजा बनाम बाल कृष्ण सोनी और अन्य 1983 (2) एसएलआर 753 और जगरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1996 (2) एसएलआर 881।

13. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, रिकॉर्ड और उनकी बहुमूल्य मदद से प्रासंगिक कानून का अध्ययन करने के बाद और पूरे मामले पर विचार व्यक्त करने के बाद, मेरे विचार से, तत्काल याचिका इस संदर्भ में स्वीकार करने योग्य है।

14. सबसे पहले, जैसा कि स्पष्ट है कि बीके भल्ला के मामले (सुप्रा) में विशिष्ट तथ्यों और उस मामले की परिस्थितियों में, यह देखा गया कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा की गई देरी के कारण पीड़ित नहीं किया जा सकता है। उनके मामलों को शीघ्रता से निपटाना। यदि सरकार अपने कर्मचारियों के मामलों को निपटाने में देरी के कारण उनकी शिकायत का निवारण करती है, तो आदेश को खराब नहीं माना जा सकता है।

15. क्रमिक रूप से, लीला राम सलूजा के मामले (सुप्रा) में, यह देखा गया कि किसी कर्मचारी को पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति देने का निर्णय लेने के लिए मामले के तथ्यों पर विचार करना राज्य सरकार का काम है, जब तक कि किसी भी नियम द्वारा वर्जित न हो।

16. इसी तरह, जगरूप सिंह के मामले (सुप्रा) में, इसे निम्नानुसार माना गया (पैरा 5): -

"यह सच है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाली सेवा की शर्तें विधानमंडल के एक अधिनियम या संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित की जा सकती हैं। हालांकि, ऐसे मामले में जहां वैधानिक नियम प्रख्यापित नहीं किए गए हैं, सक्षम प्राधिकरण

को कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से या मसौदा सेवा विनियमों के आधार पर शर्तें निर्धारित करने से नहीं रोका गया है। ऐसे मसौदा सेवा विनियम वैधानिक नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार, वे कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हो सकते हैं। हालाँकि, यदि नियुक्ति प्राधिकारी फ्रेम करता है कुछ नियम और उन्हें दिशानिर्देश के रूप में उपयोग करते हैं जब तक वैधानिक नियम सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार नहीं किए जाते हैं, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि इसकी कार्रवाई अवैध है या कानून के किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। वर्तमान मामले में, यह स्वीकृत स्थिति है कि राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई वैधानिक नियम नहीं बनाए गए हैं। कम से कम किसी को भी अधिसूचित नहीं किया गया है। वास्तव में, भले ही मसौदा नियम 1985 में बनाए गए थे, लेकिन इन्हें अब तक वैधानिक स्वरूप नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी ने अपने द्वारा तैयार किए गए प्रारूप नियमों के अनुसार कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करना उचित समझा है, तो कार्रवाई उचित और उचित है। यह केवल नियुक्ति प्राधिकारी पर अंकुश लगाता है। यह नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक को प्रतिबंधित करता है, यह कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और भी अधिक है कि इसके विपरीत कोई निर्देश किसी द्वारा जारी नहीं किया गया है। यदि राज्य सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी से वरिष्ठ किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इसके विपरीत कोई निर्देश जारी किया गया होता तो मामला अलग हो सकता था। वर्तमान मामले में उस प्रभाव का कोई सुझाव भी नहीं है। इस स्थिति में, उद्योग निदेशक को विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए मसौदा सेवा नियमों पर भरोसा करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"

17. संभवतः, उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में कोई भी विवाद नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे लिए, यह तत्काल विवाद में उत्तरदाताओं के बचाव में नहीं आएगा।

18. जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता सीधी भर्ती के माध्यम से 6.5.1986 को विश्लेषक के पद पर शामिल हुआ था। निजी प्रतिवादी नंबर 3, जो वरिष्ठ विश्लेषणात्मक सहायक के रूप में कनिष्ठ पद पर कार्यरत

था, को बाद में आदेश (अनुलग्नक पी 2) के माध्यम से 17.12.1986 को विश्लेषक के पद पर पदोन्नत किया गया था। 16.9.1988 को सशर्त आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी3) पारित होने तक वह याचिकाकर्ता से कनिष्ठ बने रहे, जिससे उन्हें पूर्वव्यापी पदोन्नति प्रदान की गई, जो इस प्रकार है: -

"श्री कुसुम कुमार, वरिष्ठ विश्लेषणात्मक सहायक, जिन्हें इस कार्यालय आदेश संख्या 11/9-पीएम-लैब-86/2463-66 दिनांक 18.12.86 द्वारा विश्लेषक के पद पर पदोन्नत किया गया था, अब 30.10.1984 से विश्लेषक के रूप में पदोन्नत किया गया है। हरियाणा सरकार के ज्ञापन संख्या 12/59/87-2HBII/1679 दिनांक 14.9.88 की अनुपालना में इस शर्त के साथ कि उन्हें 30.10.86 से 17.12.86 तक केवल वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन एरियर उन्हें वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकती क्योंकि उन्होंने वास्तव में इस अवधि के लिए इस पद पर काम नहीं किया है।"

19. इस प्रकार रिकॉर्ड पर स्थिति होने के कारण, अब संक्षिप्त और महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि महत्वपूर्ण है, जो इस याचिका में निर्धारण के लिए उठता है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी नंबर 3, जो माना जाता है कि विश्लेषक के कैडर में याचिकाकर्ता से कनिष्ठ था, क्या उसे (याचिकाकर्ता को) उससे कनिष्ठ बनाकर पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नत किया जा सकता है, आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी 3) के माध्यम से, वह भी बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए या इस संबंध में उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना?

20. पार्टियों के विद्वान वकील के प्रतिद्वंद्वी तर्कों को ध्यान में रखते हुए, मेरे लिए, उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक होना चाहिए।

21. यहां जो विवादित नहीं है वह यह है कि प्रतिवादी नंबर 3 सहायक सार्वजनिक विश्लेषक के आगे के पदोन्नति पद से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त

करने पर 18.2.2010 को पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। प्रासंगिक समय में संकेतित संवर्ग पर कोई वैधानिक सेवा नियम लागू नहीं था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कार्यकारी निर्देशों (अनुलग्नक पी 9) के अनुसार, संकेतित कैडर में 75% पद सीधी भर्ती से भरे जाने थे, जबकि शेष 25% निचले पदों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने थे। जैसा कि आधिकारिक उत्तरदाताओं ने 1985 के सीडब्ल्यूपी संख्या 4286 में दायर अपने लिखित बयान (अनुलग्नक पी 10) में स्वीकार किया था, 1985 तक पदोन्नत कोटा में विश्लेषक का कोई पद नहीं था। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के अनुसार, यह पद तब से खाली पड़ा था। 1982 में एनालिस्ट के प्रमोशनल कोटे में। आधिकारिक उत्तरदाता अपने रुख को साबित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं कि विश्लेषक कैडर के पदोन्नति कोटे में पद वर्ष 1982 में खाली पड़ा था। उसी के अभाव में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ (जेएस खेहर, उनके आधिपत्य के रूप में)) दिनांक 3.11.2004 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसका ऑपरेटिव हिस्सा इस प्रकार है: -

"मैंने संशोधित लिखित बयान पढ़ लिया है। यह उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के उपरोक्त दावे को झुठलाता है। स्पष्ट और स्पष्ट तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के विद्वान वकील को एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। 30.10.1984 और 6.5.1986 को विश्लेषक/जूनियर वैज्ञानिक अधिकारी के संयुक्त कैडर में 18 कैडर पदों को भरने के तरीके को दर्शाया गया है। उत्तरदाताओं को उपरोक्त तिथियों पर उपरोक्त संयुक्त कैडर की सटीक कैडर ताकत को चित्रित करने का निर्देश दिया गया है। .

17.11.2004 को पुनः सूची।

इस आदेश की प्रति इस न्यायालय से जुड़े न्यायालय सचिव के हस्ताक्षर के तहत प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील को प्रस्तुत की जाएगी।"

22. इसके अनुसरण में, निदेशक (प्रतिवादी संख्या 2) के उप निदेशक (पोषण) कार्यालय डॉ. आभा कुलश्रेष्ठ ने 22.12.2004 को एक हलफनामा

दायर किया, जिसमें दर्शाया गया कि 30.10.1984 से 6.5.1986 तक की अवधि के दौरान, 8 विश्लेषक के पद, जेएसओ के 6 पद सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरे गए थे और कैडर में चार पद खाली पड़े थे, जिनमें से तीन पद विश्लेषक के लिए थे और एक पद जेएसओ के लिए था, उन्होंने खुलासा किया है- कम लेकिन और अधिक छुपाया. सीधी भर्ती या प्रमोशनल कोटा की रिक्ति को मंजूरी देने के बजाय, उन्होंने विश्लेषक और जेएसओ के पदों को मिलाकर चीजों को गहराई से भ्रमित करने की कोशिश की है, जो कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग विश्लेषक से जुड़े परिशिष्ट-डी के अनुसार विभिन्न संवर्गों में पूरी तरह से अलग पद हैं। स्टाफ नियम.

23. इतना ही नहीं, रिकॉर्ड पर कोई अन्य ठोस साक्ष्य/सामग्री भी सामने नहीं आई है जो दूर-दूर तक यह सुझाव दे कि विश्लेषक के कैडर में पदोन्नति कोटा का कोई भी पद वर्ष 1982 में रिक्त था, जिस पर (पद) प्रतिवादी नंबर 3 था। 30.10.1984 से पदोन्नत किया गया। इसके अलावा, यह एक खुला रहस्य बना हुआ है कि यदि विश्लेषक के कैडर में पदोन्नति कोटा में पद 1982 से खाली था, तो कोई ठोस स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पर नहीं आ रहा है कि प्रतिवादी नंबर 3 को 1982 से पदोन्नत क्यों नहीं किया गया और बाद में उन्हें 30.10.1984 से पदोन्नत क्यों किया गया। यह तथ्य याचिकाकर्ता के मामले की पुष्टि करता है कि यद्यपि प्रतिवादी नंबर 3 को 17.12.1986 को आदेश (अनुलग्नक पी 2) के माध्यम से सही ढंग से पदोन्नत किया गया था, लेकिन बाद में, उसे 30.10.1984 से लागू आदेश (अनुलग्नक) के माध्यम से पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नत किया गया था। P3) अवैध और मनमाने तरीके से। एक बार, आधिकारिक उत्तरदाता ठोस सबूतों से यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहे कि विश्लेषक के कैडर में पदोन्नति कोटा का कोई भी पद 1982 से खाली था, लेकिन लिखित बयान (अनुलग्नक पी 10) में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि विश्लेषक के कैडर में पदोन्नति कोटा में कोई पद नहीं था। 1985 तक उपलब्ध था, उस स्थिति में, यह नहीं कहा जा सकता है और आधिकारिक उत्तरदाताओं को यह

कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि प्रतिवादी नंबर 3 को इस संबंध में 30.10.1984 से पूर्वव्यापी पदोन्नति प्रदान की गई थी।

24. बात यहीं ख़त्म नहीं होती. आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी3) के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 3, जिसे पहले 17.12.1986 को विश्लेषक के रूप में पदोन्नत किया गया था, याचिकाकर्ता से नीचे था और 30.10.1984 से अचानक पदोन्नत कर दिया गया था। आक्षेपित आदेश में यह कहीं भी नहीं दर्शाया गया है कि प्रतिवादी नंबर 3 को 1982 से खाली पड़ी उसके कोटे की रिक्ति के विरुद्ध पदोन्नत किया गया था। इसके अलावा, यह पदोन्नति आदेश एक सशर्त आदेश है। इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर 3 को कानूनी तौर पर याचिकाकर्ता के ऊपर पूर्वव्यापी पदोन्नति नहीं दी जा सकती है, जो 6.5.1986 को विश्लेषक के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से शामिल हुआ था, जब प्रतिवादी नंबर 3 का संकेतित कैडर में जन्म भी नहीं हुआ था। यह मामला पूर्ण नहीं है और अच्छी तरह से सुलझ गया है।

25. बिहार राज्य के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समान प्रश्न का निर्णय लिया गया । सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की तुलना में वरिष्ठता और पदोन्नति की अवधारणा पर विचार करने के बाद, यह फैसला सुनाया गया (पैरा 12) निम्नानुसार: -

"वर्तमान मामले में, पदोन्नत उत्तरदाताओं 6 से 23 का जन्म उस समय बिहार इंजीनियरिंग सेवा, द्वितीय श्रेणी में सहायक अभियंता के कैडर में नहीं हुआ था, जब उत्तरदाताओं 1 से 5 को सीधे सहायक अभियंता के पद पर भर्ती किया गया था और इस तरह वे उत्तरदाताओं 1 से 5 तक सहायक अभियंताओं की सेवा में वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है। यह अच्छी तरह से तय है कि किसी भी व्यक्ति को उस तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नत नहीं किया जा सकता है जब वह कैडर में पैदा नहीं हुआ था ताकि दूसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यह अच्छी तरह से है इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा तय किया गया कि समान ग्रेड के सदस्यों के बीच वरिष्ठता सेवा में उनके प्रारंभिक प्रवेश की तारीख से मानी जाती है। दूसरे शब्दों

में, बिहार इंजीनियरिंग सेवा, द्वितीय श्रेणी के सहायक अभियंताओं के बीच वरिष्ठता पर विचार किया जाएगा। सहायक अभियंता के रूप में प्रदान की गई सेवा की अवधि की तारीख। कानून में यह स्थिति होने के कारण उत्तरदाताओं 6 से 23 को आक्षेपित सरकारी आदेशों द्वारा उत्तरदाताओं 1 से 5 से वरिष्ठ नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने उत्तरदाताओं 1 से 5 के बाद पदोन्नति द्वारा उक्त सेवा में प्रवेश किया था। सीधी भर्ती के कोटे में सीधे भर्ती किये गये। अनुलग्नक 8, 9 और 10 में दिए गए विवादित सरकारी आदेशों को रद्द करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय अपवादहीन है।"

26. इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क कि आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी 3) मनमाना और अवैध है, काफी बल रखता है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के विपरीत तर्क "स्ट्रिक्टो सेंसु" बिहार राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुपात के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में अस्वीकार किए जाने योग्य हैं । मामला (सुप्रा) "म्यूटैटिस म्यूटैंडिस" इस मामले के तथ्यों पर लागू होता है और मौजूदा समस्या का पूरा जवाब है।

27. इस मामले का एक और पहलू भी है, जिसे अलग नजरिये से देखा जा सकता है. जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता 6.5.1986 को सीधी भर्ती के माध्यम से विश्लेषक के पद पर शामिल हुआ, जब प्रतिवादी नंबर 3 का विश्लेषक के कैडर में जन्म भी नहीं हुआ था। वह वरिष्ठ विश्लेषणात्मक सहायक के कनिष्ठ पद पर कार्यरत थे और उन्हें आदेश (अनुलग्नक पी2) के माध्यम से 17.12.1986 को पदोन्नत किया गया था। वह याचिकाकर्ता से जूनियर रहे। एक अच्छी सुबह, आधिकारिक उत्तरदाताओं ने अचानक 30.10.1984 से प्रतिवादी नंबर 3 को पूर्वव्यापी पदोन्नति दे दी, जिससे याचिकाकर्ता उनसे कनिष्ठ हो गया, वह भी बिना कोई नोटिस जारी किए या उन्हें (याचिकाकर्ता) सुनने का अवसर प्रदान किए बिना। इसका मतलब है, आधिकारिक

उत्तरदाताओं ने पूरी तरह से ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत और प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया है।

28. इसी तरह का एक मामला इंदु भूषण द्विवेदी बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2010) 11 एससीसी 278 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था और इस पर निम्नानुसार फैसला सुनाया गया था: -

"न्याय के बुनियादी सिद्धांतों में से एक यह है कि किसी को भी बिना सुने निंदा नहीं की जा सकती है और किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उसे खुद को हराने या अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता है। एक सामान्य नियम के रूप में, एक प्राधिकारी को पार्टियों के बीच मामले का निर्णय करने का कार्य सौंपा गया है या ऐसा आदेश देने का अधिकार दिया गया है जो किसी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या नागरिक परिणामों के साथ उससे मिलने जाता है, प्राकृतिक न्याय के बुनियादी नियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य है, जिसमें वह भी शामिल है जो महत्वपूर्ण होना चाहिए। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध उपयोग किए जाने के बारे में उसे बताया जाना चाहिए और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। सुनवाई का यह अनपेक्षित अधिकार एक उचित निर्णय के लिए मौलिक है, जो कानून के शासन की अवधारणा का एक अभिन्न अंग है। यह अधिकार इसकी जड़ें निष्पक्ष प्रक्रिया की धारणा में हैं। यह संबंधित प्राधिकारी का ध्यान उस कारण की अनदेखी न करने की अनिवार्य आवश्यकता की ओर आकर्षित करता है जो दूसरे पक्ष द्वारा अपने निर्णय पर आने से पहले दिखाया जा सकता है।
नियोक्ता को न केवल कर्मचारी को कदाचार के विशिष्ट आरोपों से अवगत कराने की आवश्यकता है, बल्कि उसके खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री का खुलासा करने और उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने या अपना बचाव करने का उचित अवसर देने की भी आवश्यकता है। यदि नियोक्ता कर्मचारी के लिए प्रतिकूल कुछ सामग्री का उपयोग करता है जिसके बारे में कर्मचारी को नोटिस नहीं दिया जाता है, तो अंतिम निर्णय ऑडी अल्टरम पार्टम के नियम के उल्लंघन के आधार पर रद्द हो जाता है। भले ही ऐसे

कोई वैधानिक नियम नहीं हैं जो किसी दोषी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच को नियंत्रित करते हों, नियोक्ता प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य है।"

29. इस प्रकार किसी भी कोण से देखा जाए और यदि यहां ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों, परिस्थितियों और कानूनी स्थिति की समग्रता को एक साथ रखा जाए, तो, मेरे लिए, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि आधिकारिक उत्तरदाताओं ने पूर्वव्यापी पदोन्नति देने में गहरी कानूनी त्रुटि की है प्रतिवादी नंबर 3 के प्रति एक पक्षीय, याचिकाकर्ता को उससे कनिष्ठ बना दिया गया, उसे कोई नोटिस जारी किए बिना इस संबंध में याचिकाकर्ता के साथ बड़ा अन्याय किया गया। इसका मतलब यह है कि, आक्षेपित पदोन्नति आदेश (अनुलग्नक पी 3) न केवल मनमाना, अवैध है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी खिलाफ है, जिसे मामले की प्राप्त परिस्थितियों में कानूनी रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता है।

30. विचार करने योग्य कोई अन्य कानूनी बिंदु, पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा न तो आग्रह किया गया है और न ही दबाया गया है।

31. उपरोक्त कारणों के आलोक में तत्काल याचिका लागत सहित स्वीकार की जाती है। नतीजतन, विवादित आदेश (अनुलग्नक पी3) को रद्द किया जाता है।

32. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि स्वाभाविक परिणाम और अनुपालन तदनुसार होंगे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर यमुनानगर